



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 28, 2014/कार्तिक 6, 1936

No. 258]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2014/KARTIKA 6, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

जांच शुरुआत

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2014

**विषय :** चीन जन. गण., थाइलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “मेलामाइन टेबलवेयर एवं किचनवेयर” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत— संबंधी

**फा.सं. 14/10/2014- डीजीएडी:** मैसर्स हैमिल्टन हाउसवेयर्स प्रा. लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें चीन जन. गण., थाइलैंड और वियतनाम (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “मेलामाइन टेबलवेयर एवं किचनवेयर” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

## **विचाराधीन उत्पाद**

2. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद मेलामाइन मोल्लिंग यौगिक (एमएमसी) से विनिर्मित “मेलामाइन टेबलवेयर एवं किचनवेयर” है। मेलामाइन मोल्लिंग यौगिक फॉर्मेलिडहाइड – मेलामाइन रेज़िन (70%), सेल्युलोस

(30%), टाइटेनियम डाइऑक्साइड और ज़िंक स्टाइरेट का संघटन है। संबद्ध वस्तु का कोई अनन्य वर्गीकरण नहीं है और वह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत है। इसका आयात विभिन्न एचएस कोडों अर्थात् 39241010, 39241090, 39249090, 39264049, 39269099 के अंतर्गत किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एचएस कोड केवल सांकेतिक हैं और सभी परिस्थितियों में उत्पाद विवरण ही प्रभावी रहेगा।

3. संबद्ध वस्तु का उपयोग खाने, पीने और खाद्य एवं पेय पदार्थ परोसने के लिए होता है। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन विभिन्न आकार और प्रकार में डिनर सेट, प्लेट्स, बाउल्स, ट्रे, मग्स, चम्मच, कोस्टर, कप एवं सॉसर सेट आदि जैसे अलग-अलग नामों से होता है। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन विभिन्न ग्रेडों में नहीं अपितु केवल अलग-अलग आकारों और डिज़ाइनों में होता है। अतः इन सभी मदों को एक व्यापक श्रेणी “मेलामाइन टेबलवेयर एवं किचनवेयर” के अंतर्गत वर्गीकृत करना और माप की इकाई भार के रूप में लेना उपयुक्त है।

### **समान वस्तु**

4. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद वास्तविक और तकनीकी विशेषताओं/उत्पाद, कार्य और प्रयोग, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण, कीमत निर्धारण, विनिर्देशन आदि की दृष्टि से तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की तुलना से यह प्रदर्शित होगा कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के संबंध में संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान हैं। उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं।

ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें नियमों के अंतर्गत “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

### **घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति**

5. मैसर्स हैमिल्टन हाउसवेयर्स प्रा. लिमिटेड ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त जानकारी को इस चरण में सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी माना जा रहा है और प्राधिकारी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में याचिकाकर्ता के उत्पादन का है। “बड़ा हिस्सा” याचिकाकर्ता योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

### **शामिल देश**

6. विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण., थाइलैंड और वियतनाम हैं।

### **सामान्य मूल्य**

7. याचिका कर्ता ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और उसने नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्वानुमान की दृष्टि से और उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अध्यधीन, नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और उसे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उपयुक्त लाभ के लिए विधिवत् समायोजित किया है।

### **निर्यात कीमत**

8. आवेदक ने डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। कमीशन, समुद्री भाड़े, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, वैट समायोजन और बैंक प्रभारों को ध्यान में रखते हुए कीमत समायोजन किए गए हैं।

## **पाटन मार्जिन**

9. कारखाना द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना की गई है जिससे संबद्ध देश के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

## **क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

10. आवेदक ने दावा किया है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है। क्षति की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है और संबद्ध आयातों में सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। आयातों से घरेलू कीमतों में काटौती हो रही है। क्षति अवधि में आयातों से घरेले कीमतों में गिरावट आई है/उनका अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन घरेलू उद्योग पर आयातों के अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में यह नोट किया गया है कि लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ जैसे मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेश पर ऋणात्मक आय हो रही है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण याचिकाकर्ता को हो रही क्षति के ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

11. और यतः, प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या पाया है कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रमाण हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराते हैं। अतः प्राधिकारी एतद्वारा कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव की जांच करने और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमों के पैरा 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को अनुवर्ती क्षति की जांच शुरू करते हैं।

## **जांच अवधि (पीओआई)**

12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित वर्तमान जांच अवधि अप्रैल 2013- मार्च, 2014 (12 माह) है। तथापि, क्षतिविश्लेषण अवधि में अप्रैल 2010 मार्च 2011, अप्रैल 2011 मार्च 2012, अप्रैल 2012 मार्च 2013 और जांच की प्रस्तावित अवधि भी शामिल है। तथापि, प्रस्तावित जांच अवधि हाल की और 12 महीने की है।

## **सूचना प्रस्तुत करना**

13. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उन के दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से निर्धारित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्न पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है :

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य विभाग**  
**चौथातल जीवनतारा बिल्डिंग,**  
**5, संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली-11001**

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना और जांच संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों के लिए उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

### **समय-सीमा**

.15 वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों ( 40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है ,तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार ,रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

.16 सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों ( 40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जाए।

### **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

.17 प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को उसके किसी भाग के संबंध में " गोपनीयता "का दावा करने के मामले में दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करने होंगे:-

(क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि)।

".18 गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों अंशों की हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपियों के भी दो सैट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

.19 गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिस के ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

.20 अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में यदि गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित करते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव न ही है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

.21 प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना

प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

.22सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

.23संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार पर उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### **सार्वजनिकफाइलकानिरीक्षण**

.24नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### **असहयोग**

.25यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास " उपलब्ध तथ्यों " के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**Department of Commerce**  
**(DirectorateGeneralofAnti-Dumping And Allied Duties)**

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2014

**Subject: Initiation of investigation for imposition of anti-dumping duty on imports of “Melamine Tableware and Kitchenware products” originating in or exported from China PR, Thailand and Vietnam.**

**F. No.14/10/2014-DGAD.**—M/s Hamilton Housewares Pvt. Limited (hereinafter also referred to as the Petitioner or applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty on the imports of Melamine Tableware and Kitchenware products(hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) , originating in or exported from China PR, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).

### **Product under consideration**

2. The product under consideration in the present petition is “Melamine Tableware and Kitchenware products” manufactured from Melamine Molding Compound (MMC). The melamine molding compound is a composition of Formaldehyde – Melamine Resin (70%), Cellulose (30%), Titanium Dioxide and Zink Stearate. Subject goods do not have a dedicated classification and is classified under Chapter 39 of Customs Tariff Act, 1975. It is imported under various HS codes namely 39241010, 39241090, 39249090, 39264049, 39269099. It has been clarified that the HS codes are only indicative and the product description shall prevail in all circumstances.

3. The subject goods are used for the purpose of eating, drinking and serving food and beverages. The product under consideration is produced in a number of different dimension and shapes called by different names such as dinner set, plates, bowls, tray, mugs, spoon, coaster, cup and saucer etc. The product under consideration is not produced in various grade but only in different shapes and designs. Therefore, it is

appropriate to classify all these items under a broad heading of “Melamine Tableware and Kitchenware products” and take unit of measurement in terms of weight.

#### **Like Article**

4. The petitioner has submitted that there is no known difference in product produced by the petitioner and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. Comparison of essential product properties in respect of domestic product and imported product would show that the goods produced by the domestic industry are identical to the imported goods in terms of essential product properties. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

#### **Domestic Industry & Standing**

5. The petition has been filed by Hamilton Housewares Pvt. Limited. The information provided by the petitioner is being considered as the best available information, at this stage and as per the records available with Authority, the production of the petitioner accounts for “a major proportion” in the total production of the product under consideration in India. The petitioner satisfies the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules.

#### **Countries involved**

6. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR, Thailand and Vietnam.

#### **Normal Value**

7. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I to the Rules. The applicant has determined the normal value based on cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

#### **Export Price**

8. The applicant has determined the export price on the basis of data published by DGCI&S. Price adjustments have been claimed on account of commission, ocean freight, port expenses, inland freight, marine insurance, VAT adjustment and bank charges.

#### **Dumping Margin**

9. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of the subject country. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

#### **Injury and Causal Link**

10. The applicant has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports. The demand for the product under consideration has increased over the injury period and subject imports have increased in absolute terms. The imports are undercutting the domestic prices. The imports have suppressed/depressed the domestic prices over the injury period. With regard to consequent impact of the imports on the domestic industry, it is noted that performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as profits; return on capital employed and cash profits. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments. There is sufficient prima facie evidence of injury to the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

11. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country; injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Para 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

**Period of Investigation (POI)**

12. The Period of Investigation (POI) proposed by the applicant is April, 2013 –March, 2014 (12 Months). The injury investigation period will however cover the periods Apr'10-Mar'11, Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13 and the period of investigation. The proposed investigation period is recent enough and is a period of 12 months

**Submission of Information**

13. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority**  
**Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties**  
**Department of Commerce,**  
**Jeevan Tara Building, 4<sup>th</sup> Floor**  
**5, Parliament Street**  
**New Delhi -110001**

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**Time Limit**

15. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

**Submission of information on confidential basis**

17. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

18. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in two (2) sets of each.

19. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. The information which is claimed

to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

23. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of Public File**

24. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

25. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J K Dadoo, Designated Authority